vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- ith;u- l[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"k Z % 15 vad % 16 y[kuÅ] jfookj 28 tqykbZ 2024 l 06 vxLr 2024 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ, सीईओ ने दी पूरी जानकारी

नई दिल्ली। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में १० राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री प्रशासनिक परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे १० अनुपस्थित और २६ प्रतिभागी थे। हमारे पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुदुचेरी से अनुपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मौजूद रहीं। बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दोपहर के भोजन से पहले बारी देने का अनुरोध किया था। मैं सिर्फ तथ्य सामने रख रहा हूं, कोई व्याख्या नहीं। यह उनकी ओर से बहुत स्पष्ट अनुरोध था क्योंकि आम तौर पर हम वर्णानुक्रम में जाते। तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से। उन्होंने कहा कि हमने वास्तव में समायोजन किया और रक्षा मंत्री ने वास्तव में उन्हें गुजरात से ठीक पहले बुलाया। तो उसने अपना बयान दिया। प्रत्येक मुख्यमंत्री को सात मिनट आवंटित किए जाते हैं और स्क्रीन के शीर्ष पर बस एक घड़ी होती है जो आपको शेष समय

बताती है। तो यह सात से छह से पांच से चार से तीन हो जाता है। उसके अंत में, यह शून्य दिखाता है। शून्य। और कुछ नहीं. इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। इसके आगे उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं कुछ देर और बोलना चाहती थी, लेकिन मैं अब और नहीं बोलूंगी। बस इतना ही था। और कुछ नहीं था। उन्होंने दावा किया कि हम सबने सुना। उन्होंने अपनी बातें रखीं और हमने सम्मानपूर्वक उन बिंदुओं को सुना और नोट किया, जो एक मिनट में प्रतिबिंबित होंगे। उन्होंने कहा कि केवल इस तथ्य का उल्लेख करने के लिए कि मुख्य सचिव उपस्थित रहे और उनके जाने के बाद भी वह कमरे में थे क्योंकि उन्हें कलकत्ता के लिए उड़ान पकड़नी थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अंतिम समय में बहुत सारे लोग बाहर हो गए, मेरे पास कुछ राज्यों के भाषण हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया था – झारखंड और पुडुचेरी। सभी ने बहिष्कार के कारणों बताया हा। जिन लोगों ने भाग नहीं लिया, उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि यह उनका नुकसान है। यदि वे हमारे और उनके दोनों के लिए हों तो कमरा अधिक समृद्ध होता है। यदि वे भाग नहीं लेंगे तो किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चाहते हैं कि जिले विकास के वाहक बनें।

२०४७ में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा, नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोलते हुए कहा कि सभी राज्यों के संयुक्त प्रयासों से श्विकसित भारत २०४७श का सपना हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने १०० साल में एक बार आने वाली महामारी को हरा दिया है। हमारे लोग उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हैं। हम सभी के संयुक्त प्रयास से विकसित भारत २०४७ के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। राज्य विकसित राज्य बनाएंगे। बैठक के बाद नीति आयोग द्वारा साझा किए गए एक बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि विकसित भारत २०४७ हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास मुद्दों और नीतिगत मामलों पर चर्चा के लिए शनिवार को नीति आयोग की बैठक की अध्

यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह बदलावों, तकनीकी और भू–राजनीतिक और अवसरों का दशक है। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रगति की सीढ़ी है। नीति आयोग केंद्र का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एनडीए के सहयोगी हैं, और कई विपक्षी मुख्यमंत्री शनिवार को बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल हुईं, लेकिन वह यह आरोप लगाते हुए बाहर चली गईं कि जब उन्होंने पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधि से वंचित किए जाने का मुद्दा उठाया तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया था। लेकिन, सरकारी सूत्रों ने उनके दावे का खंडन करते हुए कहा कि उनके बोलने का समय समाप्त हो गया था और उनकी बारी दोपहर के भोजन के बाद आती।

सीएसआईआर-नेट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया

लखनऊ। राज्य के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक टीम ने सीएसआईआर–नेट परीक्षा के लिए सॉल्वर मुहैया कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और यूनिवर्सिटी के प्रमुख कर्मियों और चार आवेदकों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की एक प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि गिरोह के सदस्य आवेदकों से उनके परीक्षा के पेपर हल करने के लिए ऑनलाइन सॉल्वर की सुविधा मुहैया कराने के लिए मोटी रकम वसूलते थे। एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर एसटीएफ की टीम ने सीएसआईआर–नेट परीक्षा के दौरान मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के विधि विभाग की कंप्यूटर लैब पर छापा मारा। टीम ने एक लैपटॉप, पांच सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), दो बूटेबल पेनड्राइव, चार सीएसआईआर– यूजीसी नेट परीक्षा पहचान पत्र, तीन मोबाइल फोन, तीन आधार कार्ड, दो पैन कार्ड और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। गिरफ्तार किए गए लोगों में मेरठ में सुभारती विश्वविद्यालय के आईटी मैनेजर अरुण शर्मा, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट विनीत कुमार और ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी एनएसईआईटी के सर्वर ऑपरेटर अंकुर सैनी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए चार आवेदकों की पहचान अंकित, तमन्ना, मोनिका और ज्योति के रूप में हुई है, जो सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। जांच में पता चला कि अरुण शर्मा ने अपने कमरे में एक समानांतर सिस्टम स्थापित किया था और एनएसईआईटी कंपनी के सर्वर ऑपरेटर अंकुर सैनी और लैब असिस्टेंट विनीत कुमार की सहायता से परीक्षा सर्वर तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की थी। इसके बाद, समझौता की गई परीक्षा फाइलों को हरियाणा में अजय नामक एक साथी के साथ साझा किया गया, जिसने परीक्षा पूरी करने के लिए सॉल्वर का आयोजन किया और उन आवेदकों को समाधान वापस भेजे, जिन्होंने

इस अवैध सेवा के लिए भुगतान किया था। वित्तीय व्यवस्था में अरुण शर्मा को प्रति पेपर ५०,००० मिलते थे, जबकि अंकुर सैनी और विनीत कुमार को प्रत्येक को १०,००० का भुगतान किया जाता था। गिरोह के अन्य सदस्यों को निशाना बनाकर छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ जिले के जानी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१८(२)/३३८/३३६(३)/६१(२) और १११/३ तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा ३/५/७/६/१० और आईटी अधिनियम की धारा ६६(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मेनका गांधी ने सुल्तानपुर से सपा सांसद के निर्वाचन के खिलाफ HC का किया रुख, 43174 वोटों से हारी थीं चुनाव

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद मेनका गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर कर सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है। मेनका गांधी निषाद से ४३,१७४ मतों के अंतर से हार गई थीं। उन्होंने शनिवार को अदालत की रजिस्ट्री में चुनाव याचिका दायर की। याचिका पर ३० जुलाई को सुनवाई हो सकती है। याचिका में मेनका गांधी ने आरोप लगाया कि निषाद ने हालिया लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय प्रस्तुत हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी छिपाई थी। इसमें दावा किया गया कि निषाद के खिलाफ १२ आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में केवल आठ मामलों की जानकारी दी है। याचिका में दावा किया गया है कि निषाद ने गोरखपुर जिले के पिपराइच थाने और बड़हलगंज थाने में दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है। याचिका में उच्च न्यायालय से निषाद के निर्वाचन को रद्द करने और मेनका गांधी को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने का आग्रह किया गया है।

सम्पादकीय

उठे गहरे संदेहों की वजह

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का दायित्व निभाने वाला संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) पर भी अब संदेह से साये पड़ गए हैं। पहले पूजा खेड़कर का मामला चर्चित हुआ और फिर सोशल मीडिया पर कई संदिग्ध मामलों का जिक्र होने लगा। केंद्र सरकार ने खेड़कर की चयन प्रक्रिया संबंधी जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और उनके माता–पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इससे यूपीएससी की साख पर उठे सवालों के जवाब सामने आ पाएंगे? खेड़कर पर फर्जीवाड़ा कर विकलांग कोटा और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है। मुद्दा यह है कि क्या फर्जी सर्टिफिकेट जमा कर यूपीएससी के जरिए अपना चयन करवा लेने में लोग धड़ल्ले से कामयाब हो रहे हैं? ये बात सामने आ चुकी है कि खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा के दौरान तीन एफिडेविट जमा कराए। इनमें से एक में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया, दूसरे में बताया कि उन्हें देखने में भी समस्या है, और तीसरे में कहा कि वे ओबीसी वर्ग में न न क्रीमी लेयर कैटेगरी से आती हैं। यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को भी उन्होंने नजरअंदाज किया। इन सारे पहलुओं पर परीक्षा प्रक्रिया से विभिन्न स्तरों पर जुड़े यूपीएससी अधिकारियों का ध्यान कैसे नहीं गया, उठे गहरे संदेहों की वजह यही सवाल है। इसी बीच एक पूर्व आईएएस अधिकारी को लेकर भी ऐसा ही विवाद खड़ा हुआ है। अभिषेक सिंह २०११ बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने लोकोमोटर विकलांगता का दावा किया और यूपीएससी की चयन प्रक्रिया में छूट का लाभ लिया। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके डांस करते और जिम में कसरत करते हुए वीडियो वायरल हो गए। तो स्वाभाविक प्रश्न उठा कि आखिर इन सब बातों की किसी स्तर पर जांच की भी जाती है या नहीं? या 'सक्षम' और 'पहुंच' वाले लोग उसी तरह पास हो जाते हैं जैसा कि अब कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में धारणा बन गई है?

अग्निवीरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP Police और PAC में मिलेगा आरक्षण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार (२६ जुलाई) को घोषणा की कि राज्य अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। उनके

लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्रगति और समृद्धि के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय–समय पर किए गए सुधार किसी भी देश और समाज के लिए आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा किं पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था को सम्मानजनक स्थान दिलाने और भारत को पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए पिछले १० वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं और हर क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। योगी ने आगे बताया कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को समान महत्व देने की आवश्यकता है। सशस्त्र बल भी इस सुधार के साथ आगे बढ़े हैं। आज भारतीय सशस्त्र सेनाएं अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस हैं। यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क रिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बल इसी गति से, इस रिफ र्म के साथ आगे बढ़ सकें, इसके लिए अग्निवीर योजना को आगे बढ़ाया गया है। युवाओं के मन में उत्साह है। अग्निपथ योजना के तहत १० लाख अग्निवीर अपनी सेवाएं देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए राजनीति देश से बड़ी है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। सुधार से जुड़ी, प्रगति से, समृद्धि से जुड़ी हर चीज में बाधा डालना उनका काम है। वे ऐसा लगातार करते हैं...विपक्ष ने इस मामले पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मेरा मानना है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हुए इस सशस्त्र बल सुधार को आगे बढ़ाना चाहिए।

कारगिल वजय दिवस २०२४ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के साथ राज्य सरका खड़ी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। छद्म रुप से पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करके भारत पर युद्ध थोपने का कार्य किया था। किन्तु युद्ध का परिणाम क्या होगा यह हमारे बहादुर जवानों ने तय किया। उस समय हमारी सेना के वीर जवानों के सामने विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों के सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया ने माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सेंट्रल कमांड, कैंट के सूर्या सभागार में कारगिल विजय दिवस की २५वीं वर्षगांठ पर आयोजित 'रजत जयंती समारोह' को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन वीर नारियों और परिवारों ने कारगिल युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर भारत की पहचान जबरन एकाधिकार करने वाले देश की नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिंता प्रवृत्तते यह भारत की परंपरा है। उन्होंने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत जब दुनिया के अंदर जब सिरमौर था, तब भी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। परंतु किसी आक्रांता ने यहां आकर हमारी शांति और हमारी सद्भावना के हनन का दुस्साहस किया तो भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि के रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के साथ राज्य सरकार हमेशा खड़ी है। सीएम योगी ने कहा कि हमारा जवान किसी भी युद्ध या सीमा की सुरक्षा करते हुए

शहीद होता है, तो राज्य सरकार की ओर उसके परिवार को आज ५० लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही उस परिवार के एक सदस्य की नौकरी भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अलावा २०१७ से हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि शहीद होने वाले जवान की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस गांव, नगर, कस्बे का वह जवान होगा, वहां पर एक भव्य स्मारक, इंस्टिट्यूट या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प को इसलिए ही आगे बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडेय के पिता, राइफलमैन सुनील जंग की माता, नायक आबिद खान की माता, नायक रामकेश चंद्र यादव की पत्नी, नायक राजेंद्र यादव की पत्नी, लांस नायक अशोक कुमार यादव के बेटे, ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिन्हा, कर्नल प्रभात रंजन, कर्नल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौशिक, कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव, नायक जितेंद्र सिंह और सिपाही विनोद कुमार दुबे को सम्मानित किया। इससे पहले सीएम योगी सेंट्रल कमांड, कैंट में कारगिल विजय दिवस की २५वीं वर्षगांठ पर आयोजित 'रजत जयंती समारोह' में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमर जवानों को पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। साथ सीएम योगी ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत के वीर जवानों के शौर्य को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी और भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धाओं को नमन किया। उन्होंने लिखा 'भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य शौर्य, अद्वितीय पराक्रम एवं अप्रतिम साहस के प्रतीक 'कारगिल विजय दिवस' की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! मां भारती के सम्मान और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को नमन! भारतीय सेना की कर्तव्यनिष्ठा व त्याग की भावना पर हमें गर्व है। जय हिंद!'

भारत पर थोपा गया था कारगिल युद्धः योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल दिवस पर २६ जुलाई को शहीद सैनिकों को श्रद्धाजंलि देते हुए कहा कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। छद्म रुप से पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करके भारत पर युद्ध थोपने का कार्य किया था, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा यह हमारे बहादुर जवानों ने तय किया। उस समय हमारी सेना के वीर जवानों के सामने विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों के सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया ने माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ २६ जुलाई शुक्रवार को सेंट्रल कमांड, कैंट के सूर्या सभागार में कारगिल विजय दिवस की २५वीं वर्षगांठ पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन वीर नारियों और परिवारों ने कारगिल युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर भारत की पहचान जबरन एकाधिकार करने वाले देश की नहीं है। योगी ने कहा कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिंता प्रवृत्तते यह

भारत की परंपरा है। उन्होंने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत जब दुनिया के अंदर जब सिरमौर था, तब भी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। परंतु किसी आक्रांता ने यहां आकर हमारी शांति और हमारी सद्भावना के हनन का दुस्साहस किया तो भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि के रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के साथ राज्य सरकार हमेशा खड़ी है। योगी ने कहा कि हमारा जवान किसी भी युद्ध या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, तो राज्य सरकार की ओर उसके परिवार को आज ५० लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही उस परिवार के एक सदस्य की नौकरी भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस मौके पर सीएम योगी ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडेय के पिता, राइफलमैन सुनील जंग की माता, नायक आबिद खान की माता, नायक रामकेश चंद्र यादव की पत्नी, नायक राजेंद्र यादव की पत्नी, लांस नायक अशोक कुमार यादव के बेटे, ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिन्हा, कर्नल प्रभात रंजन, कर्नल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौशिक, कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव, नायक जितेंद्र सिंह और सिपाही विनोद कुमार दुबे को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी और भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धाओं को नमन किया।

उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र पर निगाहें

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबर्दस्त हलचल मची हुई है। बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी ने खासी सुर्खियाँ बटोरी हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब मुखर हो गए हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। इस बीच, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ३७ सांसदों के साथ लखनऊ को छोड़कर दिल्ली का रुख किया है। इस बदलती स्थिति ने २६ जुलाई को यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया है। २६ जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और इसी दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अखिलेश यादव ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी इसी दिन होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को सुलझाते हुए सहयोगी दलों का विश्वास भी प्राप्त करना होगा। सपा ने लोकसभा चुनाव में ८० में से ३७ सीटें जीतकर अपनी ताकत का परिचय दिया है, जिससे उनके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ है। इस विजय के बाद सपा अब विधानसभा में भी आक्रामक रुख अपनाने की योजना बना रही है। कांग्रेस का समर्थन भी उनकी स्थिति को मजबूत करता है। विपक्षी दलों के मुद्दों का सामना करना बीजेपी के लिए कठिन हो सकता है, खासकर जब मुद्दे बिजली कटौती, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर नेम प्लेट विवाद और ओबीसी आरक्षण जैसे प्रमुख विषयों पर हो। बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी इस समय कशमकश में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी नेताओं के बीच खींचतान जारी है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के

बीच मतभेद की चर्चा है। सहयोगी दल भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल चुके हैं। यह सीएम योगी की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन मुद्दों का समाधान करें और पार्टी तथा सहयोगी दलों के बीच सियासी रिश्ते सुधारें। लोकसभा चुनाव के बाद, अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। इन सवालों का समाधान करना और सहयोगी दलों की नाराजगी को दूर करना सीएम योगी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उधर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल २६ जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसी दिन विधानसभा सत्र की शुरुआत भी होगी, और नए राज्यपाल की नियुक्ति या कार्यकाल का विस्तार इसी दिन से पहले पूरा करना होगा। यूपी के इतिहास में किसी भी राज्यपाल को लगातार दो कार्यकाल नहीं मिले हैं, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आनंदीबेन पटेल को केंद्र की मोदी सरकार विस्तार देती है या नया राज्यपाल नियुक्त करती है। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीतने के बाद विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। शिवपाल सिंह यादव, इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर जैसे नाम इस पद के लिए सामने आ रहे हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला अपनाया था, और माना जा रहा है कि नए नेता प्रतिपक्ष को किसी दलित या गैर–यादव ओबीसी से चुना जा सकता है। २६ जुलाई का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जो प्रदेश की राजनीतिक दिशा और संभावनाओं को आकार देगा।

मानहानि के केस में राहुल गांधी ने दर्ज कराया बयान

लखनऊ। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की एमपी–एमएलए कोर्ट में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराए। कांग्रेस सांसद के खिलाफ सुल्तानपुर में गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा चल रहा है। बयान दर्ज होने के बाद राहुल वहां से अगली तारीख १२ अगस्त की लेकर चले गये। राहुल गांधी की पेशी विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के कोर्ट में हुई। पेशी के दौरान न्यायाधीश ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, क्यों चला मुकदमा? राहुल गांधी बोले कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते मुझे फंसाया गया है। मैंने बेंगलुरु के पत्रकार वार्ता में ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। इस मामले में १२ अगस्त को प्रतिवादी विजय मिश्र के अधिवक्ता की तरफ से गवाह पेश होंगे। बता दें, सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें मुकदमा चलाया जा रहा है। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबध्कि, परिवाद में आरोप है कि १५ जुलाई २०१८ को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया

था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी। परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आईपीसी की धारा ५०० के तहत सुनवाई के लिए तलब किया तो उन्होंने २० फरवरी को न्यायालय में पेश होकर जमानत करा ली थी। उन्हें पेशी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। हालांकि, आरोपों पर जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। पिछली कुछ पेशियों पर न आने के कारण मजिस्ट्रेट ने कड़ा रुख अपनाया। इस पर बीती दो जुलाई को राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने २६ जुलाई को पेश होने के लिए अवसर मांगा था। राहुल गांधी पांच महीने में दूसरी बार कोर्ट पहुंचे हैं। इससे पहले वह लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच २० फरवरी को न्यायालय में पेश हुए थे। उस समय बड़ी संख्या में अमेठी व सुल्तानपुर के लोग उनसे मिलने व देखने की इच्छा लेकर पहुंचे थे। मामला न्यायालय में पेशी का था, इसलिए राहुल आए और करीब २० मिनट में न्यायालय की प्रक्रिया पूरी हो गई। समर्थकों व विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं के नारेबाजी के बीच वह मुस्कुराते रहे और बिना कुछ बोले ही यहां से चल दिए।

कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादवः केशव प्रसाद मौय

लखनऊ। अखिलेश यादव के मोहरा बताए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से पलटवार किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने,अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा २०२७ में २०१७ दोहरायेगी, कमल खिला है खिलेगा,खिलता रहेगा। दरअसल, कपिल सिब्बल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान की खबरों पर कहा था कि बीजेपी में झगड़ा दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के बीच है। अखिलेश ने कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद तो सिर्फ मोहरा हैं। दिल से कपिल सिब्बल के साथ इंटरव्यू में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उनके फैसलों में सबका साथ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। इसमें केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मोहरा हैं। वहीं सीएम योगी आज लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक करने वाले थे। उनकी मुलाकात से ठीक पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पाठक

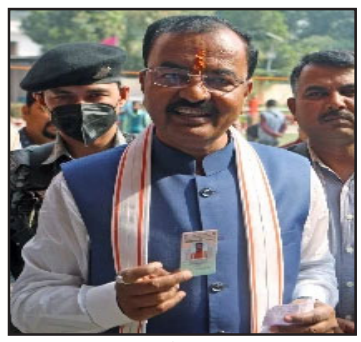

लखनऊ कैंट से विधायक भी हैं और योगी सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं। सीएम योगी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में २४ जुलाई को उन्होंने मुरादाबाद और बरेली मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। कल २५ जुलाई को उन्होंने मेरठ और प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद आज लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक चल रही है। कल जहां केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज मंडल की बैठक से गायब थे तो वहीं आज लखनऊ मंडल की बैठक से ब्रजेश पाठक ने खुद को अलग कर लिया है।

अग्निपथ योजना को लेकर अखिलेश यादव ने किया यह बड़ा ऐलान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सेवानिवृत्त 'अग्निवीरों' के लिए आरक्षण की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को दोहराया कि वह सत्ता में आते ही सैनिकों की भर्ती की इस अल्पकालिक 'अग्निपथ योजना' को २४ घंटे में रद्द कर देंगे। अखिलेश यादव ने हाल में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी लगभग सभी रैलियों में विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस) के सत्ता में आने पर 'अग्निवीर' भर्तियों को

रद्द करने का वादा किया था। उन्होंने शनिवार को भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ''सत्ता में आते ही २४ घंटे में (अग्निपथ योजना) रद्द होगी। उन्होंने इसे ''देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली भर्ती'' योजना बताया। उन्होंने सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल किए जाने की मांग करते हुए कहा, '' 'अग्निवीर' पर यही मांग हमारी, पुरानी भर्ती की फिर हो बहाली।'' मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी बल (प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी) में महत्व (वेटेज) दिया जाएगा।

दो आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, हटाए गए गाजियाबाद के DCP विवेक चंद्र यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार रात दो आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। जारी लिस्ट के मुताबिक गाजियाबाद के अपर पुलिस उपायुक्त (क्ब्च ग्रामीण) विवेक चंद्र यादव को वहां से हटाते हुए पुलिस मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक (स्थापना) सुरेंद्रनाथ तिवारी डीसीपी बनाकर गाजियाबाद भेजे गए हैं। इससे पहले सुरेंद्रनाथ तिवारी पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस अधीक्षक स्थापना के पद पर तैनात थे।

माइक बंद पर राजनीति चालू, निर्मला सीतारमण बोलीं- ममता बनर्जी का दावा पूरी तरह से झूठ

नई दिल्ली। नीति आयोग की बैठक मे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक बंद करने वाले दावे पर राजनीति चालू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पूरी तरह से झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता बनर्जी शामिल हुईं। हम सबने उन्हें सुना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक सीएम को आवंटित समय दिया गया था और उसे हर टेबल के सामने मौजूद स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह झूठ है। हर सीएम को बोलने के लिए उचित समय दिया गया। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद था जो सच नहीं है। उन्हें इसके पीछे सच बोलना चाहिए न कि फिर से झूठ पर आधारित कहानी गढ़नी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैंने नहीं देखा कि (नीति आयोग) बैठक में क्या हुआ है।श उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह तथाकथित फ्इक्र् गठबंधन बिल्कुल भी गठबंधन नहीं है क्योंकि ममता ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। वे जनता के जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं। इससे पहले ममता ने दावा किया कि मैंने

कहा कि आपको (केंद्र सरकार) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे केवल ५ मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुझसे पहले के लोगों ने १०–२० मिनट तक बात की। विपक्ष से मैं अकेली था जो भाग ले रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यह अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद हो गया। मैंने कहा आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए बजाय इसके कि आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार को अधिक गुंजाइश दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं...यह सिर्फ बंगाल का ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों का अपमान है। दरअसल, विपक्ष शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि इस बार के केंद्रीय बजट में उनका हक नहीं दिया गया है। यहीं कारण है कि वो लोग नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट भाजपा का बहिष्कार करने वाले राज्यों और लोगों के प्रति प्रतिशोध की कार्रवाई जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने इंडिया ब्ल क को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट तैयार किया है। केंद्र की भाजपा सरकार लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है।

संविधान हत्या दिवस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका, अदालत ने कहा- नोटिफिकेशन संविधान का अपमान नहीं

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने २५ जून को श्संविधान हत्या दिवसश के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत ऐसी अधिसूचना जारी करने में सरकार की राजनीतिक बुद्धि पर सवाल नहीं उठा सकती। आदेश पारित करते हुए, न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा कि २५ जून, १६७५ को आपातकाल की घोषणा के कारण हुई ज्यादतियों के संबंध में की जाने वाली घोषणा पर सरकार की नजर है। अदालत इसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। राजनीतिक दल में और २५ जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐसी अधिसूचना जारी करने में सरकार की राजनीतिक बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। पीठ ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि उन अधिसूचनाओं को रद्द किया जाना चाहिए जिनके द्वारा केंद्र सरकार ने २५ जून को श्संविधान हत्या दिवसश घोषित किया था। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि २५ जून को श्संविधान हत्या दिवसश के रूप में नामित करना बेहद अनुचित है और यह भारत के संविधान, जो कि श्भारत का संविधानश है, के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को प्रतिकूल संदेश देता है। भारत के आम लोग ज्यादा पढ़े–लिखे नहीं हैं और वे इस संबंध में ११ जुलाई, २०२४ को जारी अधिसूचना के महत्व को नहीं समझते हैं, जैसा कि १३ जुलाई, २०२४ की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है। इसके स्थान पर श्संविधान हत्या दिवसश शब्दों का प्रयोग करें। केंद्र सरकार अधिक उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर सकती थी और एक सकारात्मक शब्दावली के बारे में सोचना चाहिए था। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि सरकार ष्संविधान रक्षा दिवसष घ्शब्द का इस्तेमाल कर सकती थी क्योंकि याचिका में चुनौती दी गई गजट अधिसूचना का उद्देश्य केवल भारत के लोगों को उन ज्यादतियों की याद दिलाना है जो उस समय की सरकार द्वारा २५ जून १६७५ को आपातकाल की गई थीं।

केजीएमयू में 315 करोड़ रुपये से बनेगा अत्याधुनिक सर्जरी विभाग, 100 वर्षों की जरूरत होगी पूरी

लखनऊ। स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाने के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालयों व संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर इसकी योजना की शुरूआत राजधानी के किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय(केजीएमयू) से होगी। केजीएमयू परिसर में ही ६.६२ एकड़ क्षेत्र में ३१५ करोड़ रुपये से अत्याधुनिक सर्जरी विभाग की सात मंजिला नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस भवन में पार्किंग के लिए २ मंजिला अंडर ग्राउंड बेसमेंट तैयार किया जाएगा। इसके साथ बिल्डिंग में एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, ३०० बेड युक्त टीचिंग ह स्पिटल, १० ओटी, एक हाइब्रिड ओटी व १२ बेडेड आईसीयू, म र्चरी व अ डिटोरियम समेत अन्य सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। सर्जरी विभाग ने निर्माण व विकास कार्यों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी ऐजेंसी चयन को लेकर आवेदन भी मांगे गए हैं। निर्माण व विकास कार्यों को टर्न–की बेसिस पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट व कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में किया जाएगा। दो साल में तैयार होने वाली नई बिल्डिंग को अगले १०० वर्षों की जरूरतों के हिसाब से निर्मित व विकसित किया जाएगा।

सांसदों पर जमकर बरसे जगदीप धनखड़, 'हिट-एंड-रन स्ट्रैटर्जी' को लेकर की आलोचना

नई दिल्ली। संसद भवन में आयोजित राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को संविधान के संरक्षण और लोकतंत्र की रक्षा में संसद की सर्वोपरि भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद सदस्य (सांसद) लोकतंत्र के सबसे गंभीर संरक्षक हैं, खासकर संकट के समय में जब लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं। नए सांसदों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर लोकतंत्र में कोई संकट है, अगर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला किया जाता है, तो आपकी भूमिका निर्णायक है। उन्होंने दोहराया कि संसद को पूर्ण स्वायत्तता और अधिकार के साथ काम करना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी विषय सदन के भीतर चर्चा के लिए सीमा से बाहर नहीं है, बशर्ते कि उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि संसद अपनी प्रक्रिया, अपनी कार्यवाही के लिए सर्वोच्च है। संसद के अंदर जो कुछ भी होता है, अध्यक्ष के अलावा किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यह न तो कार्यपालिका का हो सकता है और न ही किसी अन्य संस्थान का कुछ सदस्यों के वर्तमान आचरण पर

चिंता व्यक्त करते हुए, धनखड़ ने षहिट एंड रनष रणनीति की आलोचना की, जहां सदस्य सदन में संक्षिप्त उपस्थिति से पहले और बाद में अन्य सदस्यों की बात सुने बिना मीडिया से जुड़ते हैं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को खुश करने के इरादे से व्यक्तिगत हमलों और विघटनकारी व्यवहार की बढ़ती प्रवृत्ति की भी निंदा की और चेतावनी दी, इससे बड़ी कोई विभाजनकारी गतिविधि नहीं हो सकती।

डोडा पुलिस ने जारी किए ३ आतंकियों के स्केच, सूचना देने वाले को मिलेंगे ५ लाख रुपये

नई दिल्ली। घाटी में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम तेज करते हुए, जम्मू–कश्मीर पुलिस ने तीन आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है

कि वे डोडा और डेसा इलाके के ऊपरी इलाकों में घूम रहे हैं और डेसा के उरार बागी इलाके में हाल ही में हुई आतंकी घटना में शामिल थे। पुलिस ने इनमें से प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर ५ लाख रुपये के नकद इनाम की भी घोषणा की है। जम्मू–कश्मीर पुलिस (जिला डोडा) ने आम जनता से इन आतंकवादियों की उपस्थिति या गतिविधि के बारे में निम्नलिखित संपर्क नंबरों पर जानकारी देने की अपील की है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सैन्य सूत्रों ने बताया कि शनिवार को जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कामकारी सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ब र्डर एक्शन टीम (बीएटी) के हमले को नाकाम कर दिया, जिससे सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक कैप्टन समेत चार अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि गोलीबारी में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया भी मारा गया। ठ।ज में आम तौर पर पाकिस्तानी सेना के विशेष बल के जवान और आतंकवादी शामिल होते हैं। सूत्रों ने बताया कि घंटों तक चली भीषण गोलीबारी के बीच दो घुसपैठिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में लौटने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि तीन घुसपैठियों के समूह ने उत्तरी कश्मीर जिले के त्रेहगाम सेक्टर में कुमकाडी पोस्ट के पास एक अग्रिम चौकी पर ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की।

मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में एक महिला गिरफ्तारः सीमा शुल्क विभाग

नई दिल्ली। थाईलैंड की एक महिला को मादक पदार्थ कोकीन की देश में तस्करी करने की कोशिश करने के आरोप में यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार आरोपी महिला को २३ जुलाई को बैंक क से दिल्ली आने के बाद पकड़ा गया था। विभाग ने एक बयान में बताया कि महिला के सामान और उसकी तलाशी के दौरान उसके ट्र ली बैग के अंदर रखे गए तीन क्र करी सेट से ३.१२ किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। बयान के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में ४३.१३ करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अनुसार आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है।

योगी पर दिल्ली से फैसला आ गया, यूपी में हलचल हुई तेज

लखनऊ। यूपी में सरकार के अंदर जारी पावर गेम की जंग दिल्ली तक पहुंच गई है। नीती आयोग की मीटिंग के बाद अब बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़ी बैठक होने वाली है। ये मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच होगी। इसके लिए नेताओं का पहुंचना शुरू भी हो गया है। उत्तर प्रदेश के सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। उनसे पहले यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। यानी योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों के अनुसार यूपी में सीएम को लेकर कई बदलाव नहीं होगा। लोकसभा में बीजेपी की हार पर लगातार समीक्षा चल रही है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी सदन पहुंचे। योगी आदित्यनाथ और बीएल संतोष के बीच लंबी मुलाकात हुई और राजनीति पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। १८ जुलाई के मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी एक घंटे की मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सूलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है। जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती नजर आई। इसके साथ ही २०२७ का चुनाव उन्हीं के नेतृतव में लड़ा जाएगा ऐसी बात भी कही जा रही है।

UP में BJP संकट को सुलझाएगा RSS! दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली में होंगे CM Yogi, आलाकमान के साथ भी चर्चा

लखनऊ। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद से पार्टी की स्थिति राज्य में लगातार बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस राज्य में पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, वहां उठापटक की स्थिति सबको चिंतित कर रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के बीच तनातनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। इसके अलावा उनके दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी शुक्रवार शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य में पार्टी की स्थिति और आने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा संभव है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो तनातनी की स्थिति है उसे शांत करने के लिए संघ भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तभी तो खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह आज शाम राष्ट्रीय स्वयं संघ की बैठक में हिस्सा लेंगे। यह बैठक संघ के वरिष्ठ प्रचारक संकरी लाल ने बुलाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संघ भी अब उत्तर प्रदेश में समाधान निकालने की कोशिश में जुट गया है। वहीं, पूर्वी यूपी क्षेत्र के एक वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारी ने कुछ दिन पहले मौर्य से मुलाकात की और हाल ही में राज्य भाजपा कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि आरएसएस पदाधिकारी ने मौर्य को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को उच्चतम स्तर पर उठाया जाएगा और उनसे अपनी शिकायतों को सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित न करने का आग्रह किया। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक नेता

ने संकट के समाधान के लिए राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की। बैठक में बोलते हुए मौर्य ने आदित्यनाथ पर परोक्ष हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि सरकार में आम पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में राज्य में भगवा पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे पार्टी संगठन की उपेक्षा प्रमुख कारणों में से एक थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी (एनपी) के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद के साथ मौर्य की मुलाकात ने भी यहां के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। दोनों भाजपा के गठबंधन सहयोगी थे और यहां मुलाकातों को मौर्य के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था। भाजपा सूत्रों ने यहां कहा कि आदित्यनाथ ने विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों से स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कहा था।

नेम प्लेट विवादः जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, सोमवार को होगी अगली सुनवाई

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को जारी रखा है, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भोजनालयों को मालिक या कर्मचारी के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, कोई भी स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अनिवार्यता का हवाला देते हुए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता वाले अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का कड़ा विरोध किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में बताया कि यह निर्देश हिंदू तीर्थयात्रा के दौरान

शांति बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। यह निर्देश कांवरियों की शिकायतों के बाद लागू किया गया था, जिन्होंने दुकानों और भोजनालयों के नाम के कारण भ्रम की स्थिति बताई थी। पुलिस अधिकारियों ने इन चिंताओं को दूर करने और तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया था, जिसमें कहा गया था कि हालांकि खाद्य विक्रेता अपने द्वारा परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध को छोड़कर, खाद्य विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और तीर्थयात्रियों के बीच भ्रम से बचना है।

पूर्व विधायक के गनर ने सेक्शन ऑफिसर के चालक को पीटा

लखनऊ। गोमतीनगर विपुलखंड में खाली प्लॉट के बाहर लघु शंका करने पर पूर्व विधायक के गनर ने राजस्व विभाग की सेक्शन ऑफिसर के चालक को पीट दिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला थाने पहुंचा। जहां चालक ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। वहीं, दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। गोमती नगर विस्तार में रहने वाला दीपू विपुल खंड में रहने वाली राजस्व विभाग की सेक्शन ऑफिसर नीतू सिंह की गाड़ी चलाता है। २२ जुलाई से ही उसने काम शुरू किया था। गुरुवार को सेक्शन ऑफिसर नीतू सिंह चालक दीपू के साथ बच्ची को स्कूल लेने गई थी। वहां से वापस आने के बाद उन्हें ऑफिस के लिए निकलना था। चालक घर के बाहर ही इंतजार कर रहा था। इस दौरान उसे लघु शंका महसूस हुई। वह पास के खाली प्लॉट के बाहर नाली में निवृत्त होने लगा। इसी बीच वहां बीकेटी से भाजपा के पूर्व विधायक अविनाश त्रिवेदी का गनर वहां आ गया। उसने चालक से आपत्ति की। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, नाराज गनर ने चालक दीपू को पीट दिया। शोर–शराबा सुनकर नीतू सिंह बाहर आ गई। नीतू ने जब गनर को रोकने का प्रयास किया तो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर गोमतीनगर थाने लेकर चला गया। प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर दीपक कुमार पांडेय ने बताया कि थाने में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। इसके बाद चालक ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी। दोनों पक्षों ने कार्रवाई न करने की बात कहते हुए समझौता कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया।

महिला ने लगाया बहन के साथ छेड़छाड़ का आरोप

लखनऊ। गाजीपुर में एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उसकी बहन के साथ मालिक ने छेड़छाड़ की है। गाजीपुर क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि उसकी बहन(१२) प्रभात चन्द्र जोशी के घर में काम करती हैं। आरोप है कि २१ जुलाई को उसकी बहन काम करने गयी थी, जहां पर प्रभात चन्द्र जोशी ने उसकी बहन को घर पर अकेला पाकर छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची ने इसका विरोध किया और घर पहुंचकर उसने बड़ी बहन से शिकायत की। प्रभारी निरीक्षक विकासराय का कहना है कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही हैं।

पत्नी के आत्महत्या मामले में ललितपुर के डिप्टी सीएमओ को सात साल की सजा

बांदा। बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने पत्नी के खुदकुशी करने के मामले में ललितपुर जिले में तैनात उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डिप्टी सीएमओ) को बृहस्पतिवार को सात साल कैद और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में तीस साल बाद फैसला आया है। विशेष अदालत के अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पल्लवी प्रकाश ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि ललितपुर में तैनात उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ड अशोक कुमार कथेरिया की पत्नी शकुन ने २० मार्च १९९६ को बबेरू कस्बे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी उस समय कथेरिया बांदा जिले के बबेरू कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। मृतका के भाई केपी सिंह की शिकायत के आधार पर बबेरू कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि अतिरिक्त दहेज की मांग की वजह से शकुन ने यह कदम उठाया।

बिहार सीमा पर जबरन वसूली पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई, बलिया एसपी का तबादला, डीएसपी निलंबित

लखनऊ। बिहार सीमा पर नरही क्षेत्र में ट्रक चालकों को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की गतिविधियों के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और एडिशनल एसपी का तबादला कर दिया है और सदर के डिप्टी एसपी को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई २५ जुलाई को की गई छापेमारी के बाद की गई है, जिसमें दो पुलिसकर्मियों समेत १८ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और दो अन्य को निलंबित किया गया था। सरकार के बयान में यह भी कहा गया है कि सदर के डिप्टी एसपी, नरही थाने के एसएचओ और पुलिस चौकी प्रभारी की संपत्तियों की सतर्कता जांच की जाएगी। बयान में कहा गया है कि बिहार सीमा पर पुलिसकर्मियों द्वारा वाहनों से अवैध वसूली का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस

की नीति के साथ सख्त कार्रवाई की है। इसका संज्ञान लेते हुए बलिया के पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी का तबादला कर उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है, जबकि डीएसपी सदर शुभ सूचित को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले पुलिस उप महानिरीक्षक (आजमगढ़ जोन) वैभव कृष्ण ने संवाददाताओं को बताया कि सीमा पर पुलिसकर्मियों द्वारा रंगदारी वसूलने की कई शिकायतें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (वाराणसी जोन) पीयूष मोर्डिया को मिली थीं। डीआईजी कृष्ण ने कहा कि छापेमारी के दौरान रंगदारी वसूलने वाले दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन अन्य भागने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि १६ बिचौलियों को भी हिरासत में लिया गया है। कृष्ण ने कहा कि रंगदारी वसूलने वाले गिरोह ने प्रत्येक वाहन से ५०० रुपये वसूले। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि हर रात करीब १,००० वाहन सीमा पार करते हैं, जो अवैध संचालन की सीमा को उजागर करता है।

नॉन-बायोल जिकल पीएम के लिए ढोल पीटने वाले तंत्र के रूप में काम करता है नीति आयोग, जयराम रमेश

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक की निंदा की, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक से बाहर चली गईं और दावा किया कि उन्हें उनके भाषण के बीच में गलत तरीके से रोका गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चूंकि इसकी स्थापना दस साल पहले हुई थी, नीति आयोग पीएमओ का एक संलग्न कार्यालय रहा है और गैर-जैविक पीएम के लिए ढोल बजाने वाले के रूप में कार्य किया है। इसने किसी भी तरह से सहकारी संघवाद के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाया है। इसकी कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रही है, और यह पेशेवर और स्वतंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सभी भिन्न और असहमति वाले दृष्टिकोणों को दबा देता है, जो एक खुले लोकतंत्र का सार हैं। इसकी बैठकें एक दिखावा है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति उसका व्यवहार, हालाँकि नीति आयोग का विशिष्ट है, अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बैठक में उन्हें बोलने के लिए सात मिनट का भी समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि

विपक्ष शासित राज्यों से मैं अकेला था जो वहां गया था। उन्हें मुझे ३० मिनट का समय देना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी को ५-७ मिनट में अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन मुझे बोलने के लिए ७ मिनट भी नहीं दिए गए। अपने लोगों को २० मिनट दिया गया और बाकी लोगों को ०, मैंने बैठक का बहिष्कार करके ठीक किया, मैं उन्हें बंगाल का अपमान करने नहीं दूंगी। अन्य राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां सरकार चला रहे हैं उनके साथ मैं मजबूती से खड़ी हूं।

किशोरी के साथ पड़ोसी ने की घिनौनी हरकत

लखनऊ। गुड़म्बा थाना अंतर्गत एक युवक पड़ोस में रहने वाली किशोरी (१६) को बहला-फुसला कर साथ ले गया। जहां उसने किशोरी से घिनौनी हरकत की। अगले दिन किशोरी पड़ोसी के चंगुल से बचकर अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद किशोरी की मां पड़ोसी के घर उसकी शिकायत करने गई, तो उन्हें धमकाया गया। किशोरी ने यह आरोप लगाते हुए सम्बन्धित थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक नितिश श्रीवास्तव ने बताया क्षेत्र के जानकीपुरम की रहने वाली महिला ने पड़ोसी सुनील उर्फ हॉण्डा व उसके परिवारिक सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लिखित शिकायत में महिला ने बताया कि बीते १६ जुलाई को पड़ोसी सुनील उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं लेकर चला गया गया। अगले दिन उसकी किसी तरह पड़ोसी के चंगुल से बचकर घर पहुंची। फिर बेटी परिजनों को पड़ोसी की करतूत बताई। बताया कि वह सुनील के साथ गई थी, जिसके बाद आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। बेटी की बात सुनकर महिला आरोपित के घर पहुंची। आरोप है कि शिकायत करने पर सुनील उसकी मां मुन्नी, भाई मुन्ना और विकास उसके साथ गाली-गलौज कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही हैं।

बाइक सवार बदमाश ने युवती का मोबाइल और वृद्धा से छीना मंगलसूत्र लूटा

लखनऊ। चिनहट थाना अंतर्गत बाइक सवार बदमाश युवती का मोबाइल लूट कर भाग निकले। पीड़िता बाजार से सब्जी लेकर पैदल घर लौट रही थी। पुलिस बदमाशों की पहचान के लिये घटना स्थल के आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा, बीकेटी क्षेत्र में सीतापुर हाईवे किनारे खड़ी टेंपो का इंतजार कर रही वृद्धा से कार सवार मंगल सूत्र लूटकर भाग निकाला। पीड़िता दवा लेकर घर जा रही थी। रास्ता पूछने के बहाने बदमाश ने उसे बातों में उलझाकर वारदात अंजाम दी। चिनहट प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के मुताबिक, गाजीपुर क्षेत्र के मुलायम नगर निवासी प्रमिला देवी गत १३ जुलाई की शाम करीब ७ बजे जानकी विहार स्थित मंडी से सब्जी खरीद कर पैदल घर लौट रहीं थी। एक हाथ में झोला व दूसरे में मोबाइल पकड़ा था। इसी दौरान पीछे से एक बाइक पर आये दो बदमाश मोबाइल लूट लिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तब तक बदमाश भाग निकले। सूचना पर पहुंचे डायल ११२ पुलिसकर्मियों ने बदमाशों की तलाश का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। प्रभारी निरीक्षक ने बताया लूट का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इटौंजा के शाहपुर कुनौरा निवासी संजाफिया (७०) शुक्रवार सुबह शाढ़ामऊ स्थित सौ शैया अस्पताल दवाई लेने आईं थी। दवा लेने के बाद घर लौटते समय सीतापुर हाईवे किनारे खड़ी होकर टेंपो का इंतजार कर रहीं थी। इसी दौरान कार सवार युवक उनके पास रुका और रास्ता पूछने लगा। बातों में उलझा कर आरोपी महिला का मंगल सूत्र लूट कर भाग निकला। शोर मचाने पर पहुंचे राहगीरों ने पुलिस को घटना बताई। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया पीड़िता से प्रार्थना-पत्र लेकर बदमाश की तलाश की जा रही है।

कोर्ट का आदेश गर्भपात कराना है या नहीं, यह महिला का एकाधिकार

लखनऊ। गर्भपात कराये जाने को लेकर महिलाओं के पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि एक महिला स्वयं के निर्णय पर निर्भर करेगा कि उसे अपना गर्भपात करना है, अथवा बच्चे को जन्म देना है यानि गर्भपात नहीं कराना है। कोर्ट ने कहा यह किसी और को नहीं, बल्कि उसे ही तय करना है। यह मुख्य रूप से दैहिक स्वतंत्रता के स्वींत विचार पर आधारित है। यहां महिला की सहमति सर्वोच्च है। कोर्ट ने कहा दुष्कर्म पीड़िता १५ वर्षीय नाबालिग को यह स्वयं निर्णय करना होगा कि वह गर्भधारण रखना चाहती है अथवा गर्भपात कराना चाहती है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पीड़िता और उसके माता-पिता से परामर्श के बाद ३२ सप्ताह का गर्भ समाप्त करने से जुड़े जोखिमों पर विचार कर गर्भावस्था जारी रखने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा, 'भले ही वह (महिला) गर्भधारण करने और बच्चे को गोद देने का फैसला करती है, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इसे सुनिश्चित करे कि यह काम यथासंभव निजी तौर पर किया जाए। इसी के साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि बच्चा इस देश का नागरिक होने के नाते संविधान में निहित मौलिक अधिकारों से वंचित न हो। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि गोद लेने की प्रक्रिया कुशल तरीके से की जाए और इसमें 'बच्चे का हित सर्वोत्तम' सिद्धांत का पालन किया जाए।' इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

तिहाड़ जेल में हमले में दो कैदी घायल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी स्थित तिहाड़ जेल में एक कैदी ने दो अन्य कैदियों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घायल कैदियों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा कि यह घटना शुक्रवार को जेल नंबर-६ में हुई। अधिकारी ने बताया कि दोनों कैदियों पर प्रतिद्वंद्वी समूह के एक कैदी द्वारा हमला किए जाने के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है।

लखनऊ में LPG रिफिलिंग के दौरान टंद में लगी भीषण आग

लखनऊ। राजधानी में बड़ा हादसा हुआ हुआ है। राजधनी से सटे

इटौंजा कसबे में अवैध तरीके से एलपीजी रिफिलिंग के दौरान एक मारूति वैन में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग दूर तक भागने लगे। मौके पर लोगों का मजमा लग गया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया है। वहीं आग लगने से गाड़ी राख हो गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस जांच करने की बात कह रही है। राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत

आगरा। आगरा-फिरोजाबाद राजमार्ग पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार बहन-भाई की बुधवार को मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि फिरोजाबाद जिले के थाना टूंडला के गांव मोहम्मदाबाद निवासी आसिफ अपनी १५ वर्षीय बहन और पांच वर्षीय भांजे के साथ बाइक से आगरा आ रहा था तभी गांव भागपुर के समीप ओवर ब्रिज पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि हादसे में आसिफ की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि उसकी बहन सिमरन को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के

दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। थाना एत्मादपुर प्रभारी विजय विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

भाजपा कांशीराम को अपनी सरकार से तुरंत 'भारत रत्न' दिलवाए : मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि कांशीराम जी को श्भारत रत्नश की उपाधि देने की मांग करने की बजाय भाजपा केंद्र की अपनी सरकार से उन्हें तुरंत यह सम्मान दिलवाए। मायावती ने केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश जैसी विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देने को लेकर भी सवाल उठाया। बसपा प्रमुख ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने एक संदेश में कहा, ''यूपी भाजपा के एक दलित सांसद, बसपा के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने की बजाय (भाजपा) केंद्र की सत्ता में आसीन अपनी सरकार से उन्हें तुरंत यह सम्मान दिलवाये। इसका बसपा भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना

बंद करें।'' यूपी के शाहजहांपुर (आरक्षित) संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद अरुण कुमार सागर ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की थी। मायावती ने 'एक्ष्स' पर अपने अन्य पोस्ट में बजट को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा ''एनडीए (राजग) सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश व आम जनहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात व असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश व विरोध स्वाभाविक है। हालांकि केन्द्र द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार आज कोई नई बात नहीं है। बसपा ने भी यूपी में इसे झेला है।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा, ''केन्द्रीय बजट से दुखी/पीड़ित गैर–भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। उप्र जैसी विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देना भी कितना उचित है? ''इसी पोस्ट में उन्होंने सलाह दी ''केन्द्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी है।''

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत पर एक खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रृजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य की कार्यसमिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के

जरिए जो बातें कहीं उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। १८ जुलाई के मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी एक घंटे की मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सूलह का फ मूंला सामने आ रहा है। जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती नजर आई। इसके साथ ही २०२७ का चुनाव उन्हीं के नेतृतव में लड़ा जाएगा ऐसी बात भी कही जा रही है।

कमलेश तिवारी के हत्यारोपी को मिली जमानत, पत्नी ने मांगी इच्छामृत्यु

लखनऊ। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी के हत्यारोपी को जमानत मिलने पर संगठन के पदाधिकारियों में आक्रोश फैल गया। शुक्रवार को दिवंगत नेता की पत्नी किरण तिवारी संगठन के पदाधिकारियों के साथ परिवर्तन चौक पर पहुंची, इस दौरान वह सैय्यद असीम अली को फांसी दो के नारे लगाने लगी। किरण ने कहा कि अगर आरोपी की जमानत निरस्त नहीं की गई तो वह सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ जाएंगी। फिर भी जमानत निरस्त नहीं की गई तो सरकार उन्हें इच्छामृत्यु की इजाजत दें। इस दौरान किरण तिवारी ने अपनी मांगों को लेकर लखनऊ पुलिस के माध्यम से राजपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। गौरतलब है कि राजधानी में १८ अक्टूबर २०१६ को हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की साजिश के तहत उनके कार्यालय में जाकर चाकू और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नाका थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन सितम्बर २२ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस को लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया था।

हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपित सैय्यद आसिम अली को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया है। आरोपित की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने आरोपित आसिम अली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, शीर्ष अदालत ने दलील पेश की कमलेश तिवारी हत्याकांड के १३ में ०८ आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके आधार पर सैय्यद आसिम अली को जमानत दी गई है। हालांकि, इस मामले में अब तक कुल नौ आरोपितों को जमानत दे दी गई है। बतातें चलें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमलेश तिवारी हत्याकांड में शामिल सैय्यद आसिम अली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। विविद है कि वर्ष २०१६ में सोशल मीडिया पर पैगम्बर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टीका–टिप्पणी किए जाने का मामला सामाने आया था। इसको लेकर मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना अनवारूल हक ने फतवा जारी कर कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले पर ५१ लाख और डेढ़ करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था। इसके बाद दिनदहाड़े हिंदू समाज पार्टी के कार्यालय में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि कमलेश तिवारी हत्याकांड १३ आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की गई। जिसमें दो नामजद समेत दो अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप था। शेष लोगों पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप था।

हेड कांस्टेबल को पीटा, सगे भाइयों समेत १० पर एफआईआर

लखनऊ। गौतमपल्ली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पर पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों ने हमला कर दिया। अशोक ने पड़ोसी को प्लॉट में कबाड़ जमा करने से मना किया था। आरोपियों ने उनकी पिटाई की, जब बचकर घर में भागे तो पथराव करने लगे। पीड़ित ने चिनहट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कमता न्यू पंचवटी कॉलोनी निवासी आशोक कुमार हेड कांस्टेबल हैं। उनके मकान से सटा हुआ मल्हौर निवासी मुर्तजा का प्लॉट है। जिसमें बड़ी मात्रा में कबाड़ और प्लॉस्टिक जमा की गई है। रिहायशी क लोनी में जमा किए गए कबाड़ में आग लगने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। यह बात उन्होंने मुर्तजा से कही थी। जो मुर्तजा को नगवार गुजरी। २४ जुलाई को अशोक दूध लेकर घर लौट रहे थे। तभी मुर्तजा ने भाई नासिर और राजा के साथ मिल कर हमला कर दिया। आरोपियों ने रॉड से अशोक को बुरी तरह से पीटा। झगड़ा होते देख हेड कांस्टेबल को बचाने के लिए बेटा और भतीजा दौड़ पड़े, उनके साथ भी मारपीट की गई।

आरोप है कि मुर्तजा, नासिर और राजा के बुलावे पर करीब दो दर्जन लोग आ गए और घर घेर लिया। इसके बाद अशोक के घर पर पथराव करने लगे। अशोक ने आनन–फानन पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पीआरवी पहुंची तो आरोपी भाग निकले। इंस्पेक्टर चिनहट अश्वनी चतुर्वेदी ने बताया कि अशोक के प्रार्थना पत्र पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

शाइन सिटी के सीएमडी व उसके भाई ने हड़पा स्कूल, एफआईआर

लखनऊ। बंथरा इलाके के दरोगाखेड़ा निवासी भानुप्रताप सिंह ने शाइन सिटी के सीएमडी और उसके भाई समेत तीन पर स्कूल हड़पने का आरोप लगाया है। आरोप है कि तीनों ने उसे मिलने वाले ५ करोड़ रुपये भी नहीं दिए। वहीं, छात्रों की फीस भी दबा गए। इस मामले में पीड़ित ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरोगा खेड़ा निवासी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि उनका कानपुर रोड पर ही हाम कैम्पस नाम से स्कूल है। इसके संचालन के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। भानु के स्कूल में ही सदर निवासी मो. सूफी कंटेंट डिजाइनर के पद पर काम करता था। सूफी शाइन सिटी के लिए एजेंट का भी काम करता था। भानु को दिक्कत में फंसे देख सूफी ने शाइन सिटी सीएमडी राशिद नसीम और एमडी आसिफ नसीम से मुलाकात कराई। जिन्होंने हाम कैम्पस स्कूल के संचालन की हामी भर दी। दोनों के बीच हुए समझौते के आधार पर राशिद और आसिफ नसीम को ६० तथा भानु को ४० प्रतिशत का हिस्सा तय किया गया। कागजी कार्रवाई के बाद शाइन सिटी के एमडी आसिफ नसीम ने एजेंट सैफ को संचालन का जिम्मा सौंपा। दोनों पक्षों में हुए एग्रीमेंट के तहत करीब दस करोड़ रुपये में स्कूल का सौदा किया गया। इसमें से आधी रकम ही भानु को दी गई।

बीजेपी विधायक बोले सीएम बेलगाम अफसरों के खिलाफ सबूत मांगने की बजाय कार्रवाई करे

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को मिली करारी हार की लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जिससे तीन ही बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो बेलगाम अफसर शाही ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया बाकि जो बचा था वह प्रत्याशियों के चयन में चूक और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से और खराब हो गया। लखनऊ मंडल के विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो गत लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने की यही तीन मुख्य वजह बताई गईं। मुख्यमंत्री ने विधायकों की बात सुनी और भरोसा दिलाया कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ है, सब कुछ भुलाकर अब आगे की तैयारी करें। जहां पर पार्टी को कम वोट मिले है, वहां पर संगठन को मजबूत करें। सरकार की योजनओं का प्रसार करें। पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान मिलेगा। किसी अफसर से शिकायत है तो सुबूत के साथ मुझे बताएं कार्रवाई की जाएगी। मगर योगी की सुबूत मांगने वाली बात तमाम जनप्रतिनिधीयों को समझ में नहीं आ रही है। वह पूछ रहे हैं कि हम जनता के लिये काम करें या फिर सुबूत जुटायें। मुख्यमंत्री

को हम पर इतना विश्वास होना चाहिये कि जब हम किसी अधिकारी की शिकायत करें तो उसके खिलाफ हमसे सुबूत मांगने की बजाये ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। गौरतलब हो, गत लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से मुख्यमंत्री लगातार अलग–अलग मंडलों के विधायकों से मुलाकात कर जमीनी हकीकत जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में योगी लखनऊ के अलावा सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, रायबरेली और उन्नाव के विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें लखनऊ से उत्तर क्षेत्र के विधायक नीरज बोरा, बख्शी का तालाब के विधायक योगेश शुक्ल, मोहनलालगंज से विधायक अमरेश पाल, महिलाबाद की विधायक जय देवी, पूर्व क्षेत्र के विधायक ओपी श्रीवास्तव के अलावा विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह और मुकेश शर्मा मौजूद थे। मलिहाबाद विधायक जय देवी ने बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री को पत्र देकर पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। पत्र में लिखा कि पुलिस कार्यकार्ताओं की नहीं सुनती। प्रशासन के आश्वासन पर मलिहाबाद इंस्पेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन रोक दिया, लेकिन १२ दिन हो गए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस आयुक्त फोन ही नहीं उठाते हैं। ऐसे में लोग पार्टी से कैसे जुडे रहेंगे।

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कार्यशाला में पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने सिखाई कजरी

लखनऊ। भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के गायन विभाग ने सुजान सभागार में तीन दिवसीय कजरी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पद्मश्री

मालिनी अवस्थी को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने उनका स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को इस व्याख्यान की महत्ता के बारे में समझाया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में मालिनी अवस्थी ने राग तिलक कामोद में अद्धा ताल में निबद्ध ठुमरी अंग की कजरी छात्रा–छात्राओं को सिखाई, जिसके बोल थे बैठी सोचे बृज बाम, सुनो लागे मेरो धाम। उन्होंने राग पीलू में दादरा अंग की ठुमरी हरि बिनु कारी बदरिया छाई भी सिखाई। दूसरे सत्र में दादरा कौन रंग मूंगवा कौन रंग मोतिया से कार्यशाला के पहले दिन का समापन हुआ। कार्यशाला में हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्र, तबले पर अनंत प्रजापति, ढोलक पर हर्षित शर्मा और तानपुरे पर विश्वविद्यालय की छात्रा मोनिका व निकिता ने संगत की। गायन विभाग की अध्यक्ष प्रो. सृष्टि माथुर ने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया।

कश्मीर के सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी की यह फिल्म

मुंबई। अभिनेता अविनाश तिवारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पहली फिल्म 'लैला–मजनू' कश्मीर के सिनेमाघरों में अगले महीने फिर से रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोगों के बीच फिल्म की प्रसिद्धि के कारण फिल्म को फिर से रिलीज करने का फैसला लिया गया है। फिल्म में तृप्ति डिमरी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इम्तियाज अली द्वारा लिखित और उनके भाई साजिद अली द्वारा निर्देशित यह फिल्म २०१८ में रिलीज हुई थी। फिल्म की

निर्माता अली की पूर्व पत्नी प्रीति और एक्ता कपूर हैं। तिवारी ने एक बयान में कहा, "लैल–मजनू' दो अगस्त को श्रीनगर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।" तिवारी और डिमरी २०२० में नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म 'बुलबुल' में भी साथ नजर आए थे।

बॉलीवुड में फिर से कमबैक करना चाहती है सोनम कपूर, एक्ट्रेस ने कही ये बात

मुंबई। जानीमानी अभिनेत्री और अनिल कपूर की पुत्री सोनम कपूर फिर से ब लीवुड में कमबैक करना चाहती है। सोनम कपूर ने वर्ष

२०१८ में बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की और वर्ष २०२२ में मां बनी। सोनम कपूर लंबे अरसे से फिल्मों से दूर है।सोनम कपूर ने बताया है कि वह जल्द ही फिल्मों में कमबैक करने वाली हैं। सोनम कपूर ने बताया, मैं फिर से एक्टिंग शुरू करने वाली हूं, चाहे लोग मुझे चाहें या ना चाहें। सोनम ने बताया कि उन्हें अब भी जो रोल अ फर हो रहे हैं वो २० साल की उम्र वाले किरदार हैं। सोनम कपूर ने अपनी कजिन सिस्टर्स जान्हवी कपूर और खुशी कपूर का उदाहरण देते हुए कहा, मैं जान्हवी या खुशी जितनी यंग नहीं दिखती, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि लोग मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है। भले ही मेरा एक बच्चा हो। सोनम कपूर ने कहा, मुझे हाल ही में एक लड़की की भूमिका की पेशकश की गई, जिससे उसके माता–पिता शादी करवाना चाहते हैं। मैंने बस यही सोचा, क्या आप सच में मुझे ये फिल्म अ फर करना चाहते हैं?

जियो स्टूडियोज और बी६२ स्टूडियोज की फिल्म में काम करेंगे रणवीर सिंह

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह, जियो स्टूडियोज और बी६२ स्टूडियोज की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। रणवीर सिंह अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। इस

फिल्म की शानदार कास्ट में संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी शामिल हैं।इस फिल्म का निर्माण जियो स्टूडियोज और बी६२ स्टूडियोज द्वारा किया जाएगा। यह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आदित्य धर की रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर 'उरी–द सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद दूसरी बड़ी फीचर फिल्म होगी। आदित्य धर ने उरीरू द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ ३५० करोड़ की कमाई करने वाले पहले डेब्यू डायरेक्टर के रूप में इतिहास रच दिया था। वहीं सुपरहिट रोमांटिक क मेडी र की घ्घ्और रानी की प्रेम कहानी में अपने शानदार अभिनय के बाद यह रणवीर सिंह की अगली बड़ी फीचर फिल्म हैं। ऐसे में अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक, 'कैमेलियन–किंग' रणवीर से उम्मीद की जा रही हैं कि वह आदित्य धर के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म अपना बेस्ट देंगे। इस फिल्म का निर्माण जियो स्टूडियो की ज्योति देशपांडे और लोकेश धर और आदित्य धर ने अपने बैनर बी६२ स्टूडियो के तहत किया है। इस फिल्म की शूटिंग अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है।

क्वीन ऑफ क्वींस में एक्शन अवतार में नजर आएंगी काजोल, कई भाषाओं में होगी प्रदर्शित

मुंबई। बॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री काजोल अपनी आने वाली फिल्म महारंगिनी –क्वीन ऑफ क्वींस में एक्शन अवतार में नजर आयेंगी। काजोल इन दिनों तेलुगु फिल्म निर्देशक चरण तेज उप्पलपति के साथ फिल्म महारागिनी : क्वीन आफ क्वींस में काम कर रही हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर सामने आया,

जिसमें काजोल उग्र अंदाज में दिखी। फिल्म के निर्देशक चरण तेज ने बताया कि फिल्म के सेट पर उतरने से पहले काजोल ने एक्शन को लेकर बाकायदा तैयारी की। उनके एक्शन में इमोशन भी होगा। फिल्म में काजोल मुंबई की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में पली बढ़ी महिला माया की भूमिका में होंगी। जो झोपड़पट्टी से निकलकर महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर महिला बनती है। फिल्म महारंगिनीरू क्वीन आफ क्वींस में काजोल के साथ नसीरुद्दीन शाह, प्रभु देवा और जीसू सेनगुप्ता की मुख्य भूमिका है। यह फिल्म हिंदी के साथ–साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी प्रदर्शित होगी।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lat; cktibZ

lhrkiqj

eks-9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

lqj'k ukjk;.k feJ

क्षेत्रीय सम्पादक

lkjHk dqekj] fcgkj

eks-09386075289

मो० अरशद

C;qjks phQ

eऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar@yahoo.in adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक